

चलनधिप्रबंधन ढाँचे के संबंध में RBI की अनुशंसाएँ

स्रोत: BS

चर्चा में क्यों?

भारतीय रजिस्टर बैंक (RBI) के आंतरिक कार्य समूह (IWG) ने चलनधिप्रबंधन ढाँचे (Liquidity Management Framework - LMF) की दक्षता और पूर्वानुमेयता में सुधार हेतु अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत की हैं। यह ढाँचा फरवरी 2020 से कार्यान्वयन में है।

RBI का चलनधिप्रबंधन ढाँचा (LMF) क्या है?

- **परिचय:** LMF मूल रूप से वह उपकरण-संग्रह (toolkit) है, जिसका उपयोग RBI बैंकिंग प्रणाली में **उपलब्ध नकदी की मात्रा को नियंत्रित करने**, अल्पकालिक ब्याज दरों को दशा देने और मौद्रिक नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये करता है।
- **मुख्य तंत्र (Core Mechanism):** LMF का मूल आधार **चलनधिसमायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility - LAF)** है, जो रेपो और **रिवर्स रेपो** व्यवस्था के माध्यम से आवश्यकतानुसार चलनधि को प्रवाहित (inject) या अवशोषित (absorb) करता है।
 - यह ढाँचा आमतौर पर **"कॉलडोर प्रणाली"** पर आधारित होता है, जिसमें **नीतिगत रेपो दर** बीच में स्थिति होती है। **रातोंरात भारति औसत कॉल दर (Weighted Average Call Rate - WACR)** मौद्रिक नीति का मुख्य परिचालन लक्ष्य होती है।
- **LMF के उपकरण:** इस ढाँचे में लंबी अवधि और संरचनात्मक चलनधिसमायोजन के लिये **खुले बाज़ार का परिचालन (OMO)**, **नकद आरकषति अनुपात (CRR)** और **सांघिकि चलनधि अनुपात (SLR)** जैसे अन्य उपकरण भी शामिल हैं।

RBI की अनुशंसाएँ: चलनधिप्रबंधन ढाँचे (LMF) पर

- **परिचालन लक्ष्य के रूप में WACR को जारी रखना:** WG ने सुझाव दिया है कि रातोंरात WACR को मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य बनाए रखा जाए।
 - **कारण:** WACR का अन्य कोलैटरल युक्त मनी मार्केट दरों के साथ उच्च सहसंबंध (correlation) पाया गया है।
 - यह मौद्रिक नीतिसंकेतों के प्रभावी संप्रेषण (transmission) हेतु एक विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है।
- **14-दिन के VRR/VRRR नीलामी को समाप्त करना: 14-दिन के प्रविर्ती दर रेपो (VRR) और प्रविर्ती दर रिवर्स रेपो (VRRR)** नीलामियों को अस्थायी चलनधिप्रबंधन के प्राथमिक साधन के रूप में समाप्त करने की सफ़ारिश की गई है।
 - इसके स्थान पर RBI को **7-दिन के रेपो/रिवर्स रेपो** और **रातोंरात से लेकर 14 दिन** तक की अवधि वाले अन्य ऑपरेशनों के माध्यम से अस्थायी चलनधि का प्रबंधन करना चाहिये।
 - **कारण:** 14-दिन की VRR/VRRR नीलामियों में कम भागीदारी देखी गई है क्योंकि बैंक अल्पकालिक साधनों जैसे **कस्थायी जमा सुविधा (SDF)** को प्राथमिकता देते हैं।
 - अल्पकालिक परिचालन चलनधि आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं।
- **रेपो/रिवर्स रेपो संचालन के लिये पूर्व सूचना: RBI को रेपो या रिवर्स रेपो संचालन की कम से कम एक दिन पूर्व सूचना प्रदान करनी चाहिये।**
 - यदि आवश्यक हो, तो RBI वर्तमान चलनधिस्थितियों के अनुसार उसी दिन भी संचालन कर सकता है।
 - **कारण:** पूर्व सूचना से बाज़ार में अनिश्चितता घटती है और मनी मार्केट दरें स्थिर बनी रहती हैं।
- **न्यूनतम CRR आवश्यकता:** RBI को 90% दैनिक न्यूनतम CRR बनाए रखने की आवश्यकता को जारी रखना चाहिये।
 - **कारण:** यह सुनिश्चित करता है कि बैंक पर्याप्त भंडार बनाए रखें, जिससे चलनधिकी कमी से बचा जा सके।

RBI के LMF से संबंधित प्रमुख पद:

- **भारति औसत कॉल दर (Weighted Average Call Rate- WACR):** यह वह औसत ब्याज दर है जिस पर बैंक कॉल मनी मार्केट में एक दिन (रात भर) के लिये एक-दूसरे से धन उधार लेते हैं और उधार देते हैं, जो लेन-देन की मात्रा के आधार पर भारति होती है।
 - मौद्रिक नीति के लिये RBI का मुख्य परिचालन लक्ष्य अल्पकालिक ब्याज दरों का संकेत देना है।
- **परिवर्तनीय दर रेपो (VRR):** यह RBI की एक लिखित (Instrument) है जिसका उपयोग **अल्पकालिक चलनधिप्रबंधन के लिये किया जाता है**। स्थिर रेपो के विपरीत, जहाँ दर पूर्व-निर्धारित होती है, VRR बाज़ार की माँग के आधार पर उधार दर निर्धारित करने के लिए नीलामी तंत्र का

उपयोग करता है।

- **परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR):** यह एक मौद्रिक नीति लिखित है जिसका उपयोग RBI द्वारा नीलामी के माध्यम से अतिरिक्त चलनधियों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, जहाँ बैंक RBI के पास अल्पकालिक जमा रखने के लिए परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बोली लगाते हैं तथा बदले में ब्याज कमाते हैं।
 - नियत रिवर्स रेपो दर के विपरीत, VRRR दरें नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से तय होती हैं, जिससे बाजार की शक्तियाँ दर निर्धारण में भूमिका निभा पाती हैं और RBI को अतिरिक्त चलनधियों को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में सहायता मिलती है।



मौद्रिक नीति की मात्रात्मक लिखतें

QUANTITATIVE INSTRUMENTS OF MONETARY POLICY



चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)

- रेपो दर (RR): वह दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। यहाँ, RBI प्रतिभूतियों की खरीद करता है।
- रिवर्स रेपो दर: वह दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। रेपो दर के विपरीत।
- यदि RBI सख्त मौद्रिक नीति का संकेत देना चाहता है, तो वह रेपो दर में वृद्धि करेगा; बैंक अपनी उधारी दरों में वृद्धि करेंगे।

बैंक दर

- यह एक दीर्घकालिक दर है (रेपो दर अल्पकालिक है) जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को धन उधार देता है।
- बैंक दर में वृद्धि से ऋण/जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि होगी और इसी तरह इसमें कमी से ऋण/जमा पर ब्याज दरों में कटौती होगी।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)

- SLR जमाओं की न्यूनतम हिस्सेदारी है जो वाणिज्यिक बैंकों को अभारित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी एवं स्वर्ण जैसी सुरक्षित व चल आस्तियों में रखना होता है।
- यदि RBI मौद्रिक नीति को सख्त करना चाहता है, तो वह SLR में वृद्धि करेगा।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

- बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास नकदी के रूप में रखना आवश्यक है।
- CRR में वृद्धि के साथ ही बैंक ऋण की दरों में वृद्धि कर देते हैं।



खुला बाजार परिचालन (OMOs)

- इनमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि को इंजेक्ट/अवशोषित करने के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री शामिल है।



Drishti IAS

?????? ???? ?????:

?????. तरलता प्रबंधन और मौद्रिक नीति के सुचारू संचरण को सुनिश्चित करने में तरलता समायोजन फ्रेमवर्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rbi-s-recommendations-on-liquidity-management-framework>

